

संपादकीय

इंटरनेट पर बंदिश

हालिया किसान आंदोलन के चलते हरियाणा व पंजाब में इंटरनेट पर लगी पारंपरी से एक बार किर सवाल उठा है कि क्या कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर लाखों नागरिकों का जीवन बाधित किया जा सकता है? सही मायनों में आधुनिक पुण में इंटरनेट जीवन प्रबाह का पर्याय बनकर उमरा है। यहाँ तक कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच भारतीय संक्षिप्त के तहत दिया गया एक भौलिक अधिकार है। एक मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर इंटरनेट के इसी माल पर प्रतिशंख लगाती है तो वह अस्तायी, एक दायरे में सीमित, कानूनी तौर पर वैध और अपरिहार्य होना चाहिए। एक संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इंटरनेट प्रतिशंख से जुड़े सरकार के फैसलों पर सवालिया निशान लगाते हुए इस मामले में ज्यादा पारदर्शिता अपनाने की जरूरत बनायी। हालांकि, अक्षर सरकार की दलील होती है कि यह प्रतिशंख सुरक्षा-कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए लगाया गया। ऐसे मारत समेत हुनिया के नामा देशों में यह बहस पुरानी है कि इंटरनेट पर प्रतिशंख क्य और क्यों लगाया जाना चाहिए। दरअसल, इससे न केवल नागरिकों की दिनचर्या पुरी तरह प्रभावित होती है बल्कि काशोधार को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। आजकल जब छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में लगे हैं तो उनकी परेशानियों का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। देश के विभिन्न भागों में गाहे-ग्राहे लगने वाले इंटरनेट प्रतिशंखों को दुनिया में घड़ी गंभीरता से लिया जाता है और इसे गैर-लोकतांत्रिक कदम के

हाल ही में
पाकिस्तान में हुए चुनाव
में भी ऐसी ही बहंमारी
हुई लेकिन पहले एक
अधिकारी ने सामने
आयकर अपनी बहंमारी न
केवल कहूल की है
बल्कि खुद के लिए
सजा की मांग भी कर
दी। पाकिस्तान में आम
चुनाव हुए 10 से अधिक
दिन हो गए हैं लेकिन
किसी भी दल को पूर्ण
बहुमत न मिलने के
कारण अब तक सरकार
का गठन नहीं हुआ है।

लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा में भारत पाक

यह जनज लंस्ट्रो है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस बढ़ा लोकांत्र यी अभियन्त्रीता से एक विधि गुजर रहे हैं। भारत में लोकांत्र यी सुटीदृष्टि परंपरा रही और पाकिस्तान लोकांत्र यी लिए संघर्ष करता आया है, यह दोनों दोस्तों के बीच का बुनियादी विवर्ण है। लेकिन दोनों दोस्तों में एक बड़ी समानता यह है कि वहां पर काफियत होने वे लिए पाकिस्तान में भी बढ़ावंत रहे थे वहां रहे हैं भारत में भी देसी हो रहा है। पंजीयन पर यह पुनाव इसका ताजा उदाहरण है। पहले इस पुनाव को योखल इस बढ़ाव से दाढ़ा लाया गया कि पौदासीन अधिकारी बोला था। इसके बाद 30 जनवरी गो जब पुनाव हुए गो आप और काफ़ेस का गढ़वाल हार दिया, जबकि भाजपा गो आसानीत लिया गई। इस पुनाव में बाद बतामतों को आरिज फिरा द्या था और आप ने आरोप लगाया थे कि रिटार्निंग अधिकारी निलिम बसीही ने ही बतामतों पर देशान्तर बनाया थे। उनका एक लोडियो फूटे जी सामने आया। सुनील फैर्ट ने इस मालै के लोकांत्र यी हत्या करार दिया था और सोनेवार गो हुई

सुनवाई में सुनील कोर्ट ने अनिल वसींह ने रासीकार भी किया कि उच्चान्दे आट जातपत्रों पर निशान लगाए थे। इसके बाद गंगलार यों अदालत ने जातपत्रों की किए से गिरफ्तार को आटोरा दिए हैं, इसमें रासीक शिक्षण सभी आट जातपत्र भी रासील हैं, जिससे आप को युक्तिपूर्ण फुकार बेयर घोषित हो गए। धंडागढ़ बेयर पुनाव देश में होने वाले विद्यालयों में डिमांड नहीं हासी और इसका को लिए लगाई जारी रखी, तो सच साक्षर आ गया। लेकिन इससे निष्पत्ति और पारदर्शी पुनाव या प्रश्नपत्र तो बग ही गए हैं। और सबसे बड़ा सामिया निशान तो इस बात पर है कि एक सज्जा के द्वाये में बृतानी संस्कारी और अधिकारियों को बैंझानी करने दी जा रही है। छाल ही ने पाफिक्सान में हुए पुनाव में भी ऐसी ही बैंझानी हुई। लेकिन वहाँ एक अधिकारी ने सामने आकर अपनी बैंझानी न कीबल पक्षजूल की है, बल्कि सुखू के लिए सज्जा परीं बांग भी कर दी। पाफिक्सान में आज पुनाव हुआ 10 से अधिक दिन हो गए हैं,

रहे हैं कि उन्होंने देश परी पीस में लगा घोपा है। मैंने जो अवाया किया है उसके लिए सूची ताड़ियों किया जाना चाहिए और इन अवायों में रामिल अवाय ल्योप्रिया को भी उत्तम होती चाहिए। यक्षिणीनर पद्मा ने यह भी पढ़ा था कि वे 1971 बाला दौर किया नहीं देखना चाहते हैं। गरीबल है कि 1971 में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था एवं यहाँ कि तब भी रोटे सुनील्कुरुषड्कान के धूपावाने द्वारा इसका फैक्टरीन की सीध्या तात्पारी थी इसके बाद जो लगुआ हुआ उत्तम है। इश्वरिया तसे से सब वाकियां हैं। पाकिस्तान यह 'यायतव्र', सैंस तंत्र और तात्पारी पर धारित हो गई। इस ल्योप्रिया वाली इश्वरिया तसे से फौरा सत्यका न लेना चाहें, लेकिये यक्षिणीनर पद्मा ने एक वास्तविक उत्तम लोगों को दिखा दिया है जो ईश्वरायी की साथ लोकप्रिय हैं। यह याद रखना चाहिए कि आजादी के 75-76 वर्षों माफिस्तान लोकप्रिय के लिए तात्पारा रहा है, सीध्या तानाशाही ने वहाँ लोकप्रिय की जड़ों पर

वास—यार युप्रमल और दूसी और वार्षिक फृहदा से लोकानंत्र बेड़ियों में जगजा गया। डालापिण्डी बहाँ पी अबान इसके थावनूद लोकानंत्र पी सत्ता स्थापित हरने के लिए जूझती रही, उसने धर्म और सेना पी सत्ता के आगे अपने जीरी यह समर्पण नहीं किया। दूसरी ओर भारत के आजाही के साथ ही लोकानंत्र का पांच शोमा और 7 दशरथों में इसे विशाल लहलातो युध भें तरटील होते देखा। अफ सोसे इस बात का है कि अब अनुष्टुप्ताल के नाम पर इस घटने और मंजुरात्मा दरकार की जड़ों में वर्णविता और अविनायकावली का सक्रान्ता डाला जा रहा है। चंडीगढ़ के बाट बेईनानी के और न त गव गौंयार किए जा रहे हैं, जहाँ मुनाब प्रसिद्धि से खिलवाड़ फर रहा सत्ता पी राह बनई जा सकते। कपट और 6 दूर्ता से भरे इस शरू पी तीनी बढ़ दिए गए थे जिनका नाम न दिया गया। यह एक बड़ा सवाल है।

मोदी के रामराज्य में सुदामा के चावल पर पीआईएल

डॉ. दीपक पाचप्पोर

नारायण लोकप्रिय थीं जननी हैं— यह कफाने वाले प्रवानगांवी नरेन्द्र मोटी ने उत्तर प्रदेश के संभाल में संगलवार यौं फलियक ६ गाम संस्थिर पर शिलायास करते हुए नये तारीके से ‘यायमालिका’ पर छम्भा बोल दिया है, जो बतलाता है कि वे सरकार के खिलाफ आ रहे अदालती कर्त्तव्यों से खासे परेशान धन रहे हैं। उनकी परेशानी स्वामालिका तो है क्लेकिन फिर्सी भी देश के यार्यपालिका प्रबुद्ध द्वारा ऐसी दिप्पांगी न तो बाजीराही है और न ही रोकीरी। उन्हें अगर ‘यायमालिका’ से फिर्सी तरह ही शिलायत है तो उन्हें यह डॉकोर्ट के भीतर ही निपटाना चाहिये। उस लड़ाई को इस प्रकार से फिर्सी सार्वजनिक समाजक क्षेत्र में जाना चाहिया नहीं। वैसे मोटी यह गुरुस्ता इस लिहाज से जायज है क्लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई फैसले कोर्ट सरकार के विरुद्ध तो आये ही हैं, निकट नवीन्य के और भी सम्भालित हैं। सामाजिक मैं नीचूद पूर्व दिनों पूर्व कल्पना से निकाल गये प्रानोट हृष्णन को सच्चोदाता करते हुए मोटी ने तंज फूल के लिये रथ यह भी अचान्क हुआ जो अपने (हृष्णन) कोवल अपनी आवानाएं ही व्यापक की। आवानाओं के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया वसना यह ऐसा समय धन रहा है कि अगर आज हृष्णा होते और सुधारा उड़े हृष्ण को फैसल उत्तरपा वीडियो बनाता और पीआईएल (जनरिंग यांत्रिकी) द्वारा यह देता रखे गये तो है। मोटी निरिघा ही हाल का वह निर्याहा होगा जिसमें सुधूर यायावीरा डीवाई यंदूपूड़ यी अध्यक्षता वाली सुप्रीम फॉरेंट यी एक बैच ने मोटी सरकार द्वारा २०१७-१८ में लाये गये इलेक्ट्रोलैन (पुनार्विद्या) बोर्ड्स को रख संवैचानिक, नागरिक अविकाशों का फृहत और सूचना के अधिकार का उल्लंघनर बतलाया है। मोटी इस बात से इतेकाक नहीं रखते कि जनता को पुछ बताया जाये। वे ऐसे हर नियम से सुधूर व उनकी सरकार को दूर फर देते हैं जिसमें जनता को जायब देना मढ़े। इत्तिलिये वे भीडिया से बात नहीं करते, सुली परिवारीओं में दिस्ता नहीं लेते, फोइ जलवाल नहीं लेते। प्रवकार हों भी तो उनके अपने गोट लिये हुए अदाला असत्य पुरावर या प्रसूत जोरी जैसे सिनेमा कलाकार-गीतकार हों जो उनसे महले से दिये गये प्रसानों के आड़ पर आप धूसने के तरीकों और १८-१५ घंटे तकन पराने के बावजूद न धक्के पक्का कारण जनना चाहते हैं। ऐसे प्रायोजित सवालों के उत्तरों पर सुधूर होने वाला उनके प्रारंभणकों व समर्थकों का एक बड़ा बग है, तो मोटी को रथर सुधूर को प्रदानीकी नहीं बल्कि स्पार्टा होने की गलतावधी हो जाये, तो आरथर्य नहीं होता यादिये। यही कारण है कि देश में लोकप्राप्त या आग्रह ही नहीं बल्कि रास बदने वाला ऐतिहासिक संसद नवन उड़े जाने को ढौँडता है। इत्तिलिये वे उसे बढ़ कर सेट्रेव विस्ता बनाते हैं नये-नये परिव

की दो पूर्ण सहिताओं के साथ
दो बाह महले हुए अवानीवी
यारी की ऐसी तस्वीर थी जिनमें
दो हाँ नहीं पूरी तुलना ढाकी
गयी थी। सालाल झड़े हो
लाजिसी थे। एक दोसों की संस्कृति
में भी इस पर पर्याप्त हुई थी
यहाँ तक कि गोटी को इस
माले पर सुन् खोलना पड़ा। उन
जिनकी सरकार ने (फ्रेंच
राज्य थी) इसे दबाए रखा था
नये संसद नवन के पहले से
के दिन गाथा उनकी असेरिय
याक्का के दरारन संक्षिप्त ही सही



पुनावी योंगत थे रसरियत-खोशीर
बत लापकर सुमीन कोट्ट ने बोटी थी
ये ई-गानदारी थी बुद्धांटे थे
उत्तार कोंधें। ऐसे ही, घंटीगव
मेयर थे पुनाव में हुई धांवली
योंग उड़ोंने स्लोवाकिया की छायास
बत लापकर भाजपा को निर्विस्त्र
कर दिया। अपने उत्पादों थे
लिये ख्यालीनदृष्टि आयोग थी
सिफारिशों के अनुसार झूलतान
समर्थन मूल्य थी सांग थे लोकप
प्रदर्शन कर रहे किसानों थे
खिलाफ सुमीन कोट्ट थार
एक्सेसियरन के अध्यक्ष जब यह
गुहार लगाने जाते हैं कि, सदफर
यातायात जान थे फारवण
सुनवाई में बिल्ड से या च
आने वाले वाहिनी थे सुविधिकरण
से विरुद्ध निर्णय न दिये जाएं,
तो पंचायूद यह काफकर उड़ों
बैरंग लोटा देते हैं यि के बिंदा
न करें, फोटो देते लोगी। पूर्ववर्ती
फाई जज सरकार के मक्क में
फैसला देकर उपकृत हो सुझें
है। अनुकूल फैसला देने वाले
फोई जज राज्य सभा में हैं तो
फोई राज्यमाल बने बैठे हैं।
बोटी थी ऐसे ही न्यायालीश और
ऐसी ही न्यायपालिका याइये।
उनके पूर्णांश से पंचायूद
वाकियों से अलग हैं। वे बेड़ाक
सरकार के खिलाफ फैसले दे
रहे हैं और कोटर्लन के बाहर
मी लोगों थे कोटर्लन दे रहे हैं यि
वे निर्माण होकर सरकार यी
आलोचना पाएँ। उनकी सुस्था
के लिये नारा यी न्यायपालिका
बैठी हुई है। नाथ ही अपनी मी
प्रणाली पर मी राह दे रहे हैं यि
अपराधिक नागरियों में जमानत
देने में नियंत्री अदाजारों न यग्रता
महसूस पाएँगी हैं।



केंद्र को अब पारदर्शी चुनावी फंडिंग प्रणाली पर काम करना चाहिए

કાળાણી શક્તિ

कन्याएं शक्ति
भारतीय मुनाब एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लाखों बाताता और अनेक साजनीयिक दल राशिगल होते हैं। ये पार्टियां अपने अनियानों के विषयोंवाले के लिए व्यक्तियों और नियंत्रों के योगदान पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, एवं कोई फ़ॉर्मिंग महत्वपूर्ण नहीं। मुनाब के दौरान बहुत सारा प्रश्न बच नहीं छुपता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सारत के प्रबालनसंबंधी घटे, तो उन्होंने साजनीति में अकेले इन का उत्पन्न घोषणे कर यादा किया था। तीन साल बाद, 2017 में उन्होंने मुनाबी बांड योजना पेश की, जिसके बारे में उनका दाया था कि इससे साजनीयिक फ़ॉर्मिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, युएल लोगों ने गोपनीयता छंड और नालिंगिक अदिक्षणों के उत्तरवाचन को अदालत में धूनाती ही। पिछले हफ्तों सर्वोच्च आयातन ने मुनाबी साजनीयिक घटे को अवैध घोषित कर दिया। इस कई सले को भाजपा एवं ठिंपु प्रथाना सुरिकल हो जाता है। पर्याप्ति 2018 से प्रभावी इस योजना से स्तरात्मक दल घो क्षमता के साथ से अधिक फायदा हुआ है। और अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि मुनाबी बांड नगरियों एवं सशक्तिरी जातानारी ताक पहुंचने के अविकारण का उत्तरवाचन फ़रही है और स्विचान यी भारा 19(1)(ए) का उत्तरवाचन फ़रही है। सुन्दर आयातीय घटदूड़े ने खुले रातन के सहारे पर जोर दिया। जलातान ऐसे विषयान् पर प्रभावी बंग से

उपयोग करने के लिए राजनीतिक दलों यीं फ़ॅडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। सरकारी स्वास्थ्य बाले भारतीय स्टेट बैंक को इन बांडों को जारी करने से शेफरन और भारत के सुनाव आयोग को विवरण प्रदान करने का अधेरा दिया गया है। यह फ़ॅस्तुका पांच जर्जों के समूह ने दिया। याचिनीराओं ने जांच की फ़िल्म देखा। सुनाव बांड योजना ने संवैधानिक नियमों परों तोड़ा है, दानदाताराओं यीं भलत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने से बाहर है, दानदाताराओं यीं गोपनीयता यीं रक्ष करते हुए राज्य दान यीं अनुसारी ही है, और लोकप्राप्तिक प्रक्रियाओं यीं उतारे में डाला है। पहले, राजनीतिक दलों 20 रुपये से अधिक पत्र योगदान देने वाले दानदाताराओं यीं पहचान का सुलभता करना आवश्यक था। डालायिंग, सुनावी बांड राजनीतिक दलों यीं दानदाताराओं यीं पहचान उत्तरार्थ दिये बिना प्राप्त बन यीं रिपोर्ट करने की अनुसारी देते हैं। इन बॉइंट्स यीं ऐन 1,000 से 10 फ़रोड़ रुपये तक होती है। लोगों यीं जानना यादिए कि राजनीतिक फ़ॅडिंग पारदर्शी है या नहीं। सुनाव आजो योनाओं में से एक यह है कि इन बांडों पर शरीरों साथ यह मता लगाना फ़ाटिन है कि वैसा कहा से आता है, जिससे बन यीं ज्ञात यीं पहचान करना सुनावीपूर्ण हो जाता है। 2017 से 2022 तक यीं एक्सीआर आंडांगों पर अनुसार, इस अवधि यीं तांगन नियमों द्वारा दान यीं गई रफ़त गणि 3,299,85

कर्शेड रूपये थी। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा जाजपा
निला। पुनर्वायी बांड़ के बाब्यन से कांग्रेस पार्टी को 406.45 कर-
पये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को 109.5 कर्शेड रू-
पये और अखिल भारतीय उपमूल कांग्रेस (ज्ञाईटीसी) को 4
कर्शेड रूपये निले। एडीआर वी रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि जाजनीतिक योगदान के बारे में जानकारी अनुप्रिय-
करदाताओं को पता होना चाहिए कि जाजनीतिक ढंगों को
कहाँ से लिया जाता है। पारदर्शकों की एकी जयवाट्टी पर¹
उदात्ती है। करदाताओं को पैसा बांड़ छपने में खर्च होता है व
उस्तीवाई को उनकी विद्युति से मुनाफा होता है। इसमें दावा
गया है कि पारदाताओं को यह जानने का अविकार है
जाजनीतिक ढंगों को उन एको से लिया जाता है। अधिक पारदर्शि-
की आवश्यकता जयवाट्टी के बारे में संतोष पैदा करती
करदाताओं को पैसे का उपयोग बांड़ सुनित परने के लिए पि-
जाता है, और उनकी विद्युति से उस्तीवाई को मुनाफे को अनुप्रि-
या बाना जाता है। जनता और विद्युति ढंगों को इन दान के सांग
बारे में पता होना चाहिए। डालांपि सरकार उस्तीवाई से द
विकरण प्राप्त कर सकती है। संसद ने, सरकार ने प्रमुख फैल
एजेंसियों और विद्युति संसद चलन्सी एवं योगावनियों एवं उपका-
र्य एवं संबंधी बांड़ योजना शुरू की। बांड़ विवेकपुर एवं उन विवेक-

के रूप में पारित किया गया था। इससे पहले, कानून संवालय ने इस बात पर जोर दिया था कि बांड योजना यों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यक पालन करना चाहिए। युनाय आयोग और आरबीआई ने भी 2017 योजना के प्रावधानों का विशेष किया, लेकिन सरकार ने भाजपा के हितों को ब्यान में रखते हुए इसे लागू किया। युनाय आयोग ने 2.5 लाख राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया है, लेकिन फैशन एक छोटा प्रतिरक्षण, फैबर 2.17 प्रतिरक्षण, वर्षनान में यात्रायात प्राप्त है। युनाय पार्टीयां कर्मी भी युनाव में जाग नहीं ले सकती हैं, जबकि अप्य नीति लॉन्चिंग गतिविधियों में रामिल ही सकती है। 2019 के युनाव के दौरान राजनीतिक दलों की रिपोर्ट तोड़ रकम मिली। युनायी बांड एवं भाव्य स से 2,760, 20 फैशन एवं युनासन घटा आया। यह 2017–18 और 2018–19 में मिली स्थिर से ज्यादा रफ़ा थी। 2017–18 से 2020–21 तक, 19 राजनीतिक दलों ने लगभग 6.5 हजार फैशन रुपये के युनायी बांड युनाये। पिछले छह लोकसभा युनावों में ऊर्ध्व लगभग छह गुना बढ़ गया है जो 9,000 रुपये से बढ़कर 2019 में 55,000 फैशन रुपये हो गया था। 2018 से मार्च 2022 तक नायपा यों 57 प्रतिरक्षण घटा मिला, जबकि फैशन्स यों सिर्फ़ 10 प्रतिरक्षण ही प्राप्त हुए। उन्हीं हि हैं जिन संघर्ष पहले एवं अवसरों के विपरीत, स्वाधीन यात्रा यों ऐसे संघे पर लगाया गया।

